

2000
प्रेषक

संख्या: ——— /XXIV(6)/ 2016-4 (29)/15

नितिन सिंह भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
कुमाऊं विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग-6 (उच्च शिक्षा)

देहरादून: दिनांक 04 जनवरी, 2017

विषय:- कुमाऊं विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी परिसर भीमताल में अनुसंधान प्रयोगशाला भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- केयू/भवन-353/2015/355 दिनांक 03.09.2015 एवं पत्र संख्या-केयू/भवन-353/2016/440 दिनांक 13.05.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आयोजनागत पक्ष (Plan) में कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल के बायोटेक्नोलॉजी परिसर, भीमताल में अनुसंधान प्रयोगशाला भवन के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा गठित आंगणन रु० 249.10 लाख के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि रु० 245.26 लाख एवं अधिप्राप्ति कार्यों हेतु धनराशि रु० 2.70 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रु० 247.96 लाख के आगणनों का प्रशासकीय अनुमोदन एवं चालू वित्तीय वर्ष में प्रथम किश्त के रूप में रु० 99.18 लाख (रु० निन्यानवे लाख अटठारह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश संख्या-1097/XXVII(1)/2016 दिनांक 20 सितम्बर, 2016 में उल्लिखित निर्देशानुसार तथा निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) स्वीकृत की जा रही धनराशि का बिल जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत किया जाएगा। तत्पश्चात नियमानुसार धनराशि निर्माण एजेंसी को उपलब्ध करायी जाएगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनावश्यक धनराशि रोककर कार्य की लागत में वृद्धि नहीं की जाएगी।
- (ii) स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए ही धनराशि आहरित/व्यय की जाये। चयनित कार्यदायी संस्था को कार्यों हेतु जब अन्तिम किश्त निर्गत की जाय तो उक्त अन्तिम किश्त निर्गत करने से पूर्व उक्त कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन (Third Party Evaluation) करा लिया जाय, ताकि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
- (iii) विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि का शीघ्रातिशीघ्र उपभोग सुनिश्चित कराते हुए कार्यदायी संस्था को कार्य की प्रगति में समुचित तेजी जाने हेतु भी निर्देशित किया जाय, जिससे कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो सके। भवन की लागत का पुनरीक्षण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा तथा समय-समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) प्रश्नगत कार्य आगणन की संस्तुत लागत में ही पूर्ण करा लिया जाएगा। इस हेतु कार्यदायी संस्था से लिखित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाय तथा कार्य की प्रगति कर नोडल अधिकारी द्वारा निरन्तर अनुश्रवण कर निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण करा लिया जाय। उक्त निर्माण कार्य के आगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा, एवं किसी भी दशा में अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी।
- (v) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
- (vi) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008, डी0जी0एस0एन0डी0 की दर संबंधी शासनादेशों का पूर्ण पालन किया जाना होगा।

(vii) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकाताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(ix) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक: 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(x) कार्य प्रारम्भ करने पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- व्यय उन्हीं कार्यों/योजनाओं मर्दों पर किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा तथा समय-समय पर वित्त विभाग के निर्गत शासनादेशों में वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4- निर्माण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 475/XXVII(7)/2007 दिनांक: 15.12.2008 की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से M.O.U हस्ताक्षरित किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-261(P)XXVII(3)2016-17 दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से एवं साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट एलॉटमेंट आई0डी0 संख्या- (प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत किए जा रहे हैं।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-11 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा- आयोजनागत-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-14-कुमाऊं विश्वविद्यालय-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान की सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(नितिन सिंह भदौरिया)

अपर सचिव।

पृष्ठांकन:-1335 (1)/XXIV(6)/2016-4(29)/15, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराँय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. कुलपति, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
5. कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
10. परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नैनीताल।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)

संयुक्त सचिव।